International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.340, Volume 03, No. 02(IV), April - June, 2021, pp.181-184

भारतीय समाज और वैश्वीकरण

डॉ. झब्बू राम वर्मा*

सार

भारत सरकार की नवीन आर्थिक नीतियों में एकनीति अर्थ व्यवस्था के ग्लोबलाईजेशन की है। जिसका उद्देश्य भी भारतीय अर्थ व्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुडाव करना है। इसके अन्तर्गत सभी वस्तुओं के आयात की खुली छूट सीमा शुल्क में कभी विदेशी पूंजी के मुक्त प्रवाह की अनुमति, सेवा क्षेत्र विशेषकर बैंकिग बीमा तथा जाहाजरानी में विदेशी पूंजी के निवेश की व्यवस्था है। उदारीकरण के बाद भारत में समृद्धि तो बढ़ी है आगे बढ़ने के अवसर बढ़े है। जो भी क्षमता/योग्यता रखता है। उसे रोजगार के अवसर बढ़े है। लेकिन देखना यह है कि उदारवादी आर्थिक नीतियों का लाभ एक वर्ग विशेष तो नहीं उठा रहा है क्या धन का असमान विवतण तो नही हो रहा है विकास तो हो रहा है परन्तु किसका ? 20 प्रतिशत औद्योगिक घरानों के पास देश का 80 प्रतिशत धन है वही 80 प्रतिशत लोगो के पास देश का 20 प्रतिशत धन है पांच सितार होटल गगन चुम्बी अट्टालिकाओं और बी.आई.पी. सेज और आवासीय कालोनियों की चमक में झोपड पट्टियां कहां दिखाई देती है? बडे–बडे औद्योगिक घराने देश की शान है। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए की देश की 70 फीसदी से अधिक जनता गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है।

कुंजीशब्दः *आर्थिक नीतियों, ग्लोबलाईजेशन, भारतीय समाज, वैश्वीकरण, गरीबी रेखा।*

प्रस्तावना

वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ वस्तु सेवा पूंजी व बौद्धिक सम्पदा का अप्रतिबन्धित आदान प्रदान होता है परन्तु यह तभी सम्भव है। जब ऐसे आदान–प्रदान के मार्ग में किसी देश द्वारा अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाये और उन्हें कोई ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था संचालित करें जिसमें सभी देशों का विश्वास हो जो सर्वानुमति से नीति निर्धारिक सिद्धान्तों का निरूपण करें। सामान्य नियागो के अनुशासन में रहकर सभी देश व्यापार और निवेश का संचालन करते है। और स्वाभाविक एक ही धारा में प्रवाहित हो यही वैश्वीकरण है।

भारत सरकार की नवीन आर्थिक नीतियों में एकनीति अर्थ व्यवस्था के ग्लोब लाईजेशन की है। जिसका उद्देश्य भी भारतीय अर्थ व्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुडाव करना है। इसके अन्तर्गत सभी वस्तुओं के आयात की खुली छूट सीमा शुल्क में कभी विदेशी पूंजी के मुक्त प्रवाह की अनुमति, सेवा क्षेत्र विशेषकर बैंकिग बीमा तथा जाहाजरानी में विदेशी पूंजी के निवेश की व्यवस्था है।

वैश्वीकरण व्यापारिक माहौल की ऐसी अवधाराणा है जो पूरे विश्व को एक मंडल केन्द्र बनाने की बात करता है। इसके अन्तर्गत छः अलग–अलग आर्थिक प्रक्रियाएं शामिल है।

---

[6] सह आचार्य–समाजशास्त्र, स्व. राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाँदीकुई, दौसा, राजस्थान।

- वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार
- टेक्नोलाजी का अधिक युक्त प्रवाहः
- प्रत्यक्ष विदेश निवेश में वृद्धि
- अन्य पूंजी प्रवाह का अधिक मुक्त संचरण
- राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार लोगों की मुक्त रूप से आवाजाही
- दूनिया की वैश्वीकृत व्यवस्था के लिये उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय शासन संस्थाओं का विकास।

पिछले दस वर्षों में वैश्वीकरण और इसके प्रभावों के बारे में बदलाव चक्रीय क्रम में हुआ है। राजनीतिक दृष्टि से विचार करें तो पूर्व यूरोप और सोवियत संघ में साम्यवाद है पतन और इन देशों द्वारा लोकतांत्रिक प्रणाली तथा बाजारोन्मुख नीतिया उत्साह पूर्वक अपनाने से विजयोन्माद जैसा माहौल रहा अमेरिका में आर्थिक तेजी लंबे दौर के (साथ–साथ) हुई है। जिसके पीछे नई टेक्नोलॉजी खास तौर पर सूचना टेक्नोलोजी से उत्पादकता में आसाधरण बढ़ोत्तरी का बड़ा हाथ रहा है। ऐसी उम्मीद लगाई गई थी की वैश्वीकरण से विकास शील देशों की पंहुच औद्योगिक देशों के निर्यात बाजार तक हो जायेगी, जिससे उन्हें फायदा होगा इसके साथ यह भी उम्मीद की गई थी कि अच्छे प्रबंधन वाली सभी अर्थव्यवस्थाओं को निर्बाध रूप से पूंजी की आपूर्ति भी होती रहेगी। **लेकिन अति उत्साह से पैदा हुआ भारत का माहौल अधिक समय तक नहीं चला और 1997 के अंत में पूर्वी एशिया का अर्थिक संकट जबदस्त झटका सावित हुआ।** 1998 में रूसी मुद्रा लड़खड़ाई इसके बाद ब्राजील तुर्की व अन्य देशों की मुद्रा गड़बड़ा गई। इस संकट में नवोदित बाजार अर्थ व्यवस्थाओं की संवेदनशीलता ने वैश्वीकरण के खतरों पर ध्यान केन्द्रित कर दिया। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में तेजी का लम्बा दौर 2000 में समाप्त हो गया ऐसी टेक्नोलॉजी कम्पनियां के शेयरो के लुढ़कने और आर्थिक गतिविधियों के गिरावट से हुआ ज्यों–ज्यों नौकरियो में कमी आई औद्योगिक देशों मे वैश्वीकरण के खिलाफ आवाज उठने लगी व बेरोजगारी बडी।

वैश्वीकरण की प्रक्रिया में भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाने के लिए विकसित और विकासशील देश भी लालाहित हुऐ। इस बीच देश मे अरवपतियों की संख्या मे अप्रत्याशित वृद्धि से देश का सम्मान बढ़ा और भारत ने विगत वर्षो मे तरक्की की और हमारा देश भारत दूनिया की तीसरी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आने लगा। अमेरिकी सरकार संस्था **नेशनल इंटेलीजेंस काउंसिल और यूरोपियन यूनियंस इनस्टीट्यूट फांर सिक्युरिटी स्टडीज** ने शक्ति के तमाम जरूरी आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक पैमाने पर विमर्श के बाद भारत को अमेरिका और चीन के बाद स्थान दिया गया। और भारत यूरोप जापान रूस आदि देशो से आगे निकल गया 2025 के आते–आते भारत देश की ताकत और बढ़ जायेगी। उदारीकरण के बाद भारत में समृद्धि तो बढ़ी है आगे बढ़ने के अवसर बढ़े है। जो भी क्षमता/योग्यता रखता है। उसे रोजगार के अवसर बढ़े है।

आर्थिक महामंदी से जब दुनिया कराह रही थी अमेरिका जैसे मजबूत देश की अर्थ व्यवस्था के विकास दर नकारात्मक हो गई थी तब भी भारत की विकास यात्रा जारी रही हमारी विकास दर की मात्रा महामंदी में 5 प्रतिशत से नीचे नहीं है स्वाभाविक ही हम अपनी शक्ति के बूते टिके रहे है।

वैश्वक मंदी से निपटने में भारत की क्षमता से विकसित और दुशमन देश भी भौचक्के रह गए है। भारत के साथ व्यापारिक सम्बन्ध बनाने के लिए विकसित और विकासशील देश भी लालायित है। इस बीच देश में अरबपतियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि से देश का सम्मान बढ़ा है। अब हमारे देश में अरबपतियों की संख्या 138 हो गई है इस संख्या में प्रगति की रफ्तार काबिले तारीफ है। केवल दो वर्ष पहले देश में 100 अरबपति थे दो साल में डेढ गुणा अरबपति बढ़े है। ये डेढ गुणा लोग एकाएक तो इस ऊँचाई पर नहीं पहुंचे ये लोग पहले से ही करोड पति रहे होंगे लेकिन जिक तेजी से इनकी प्रगति हुई इससे तो साफ है कि सरकार ने इनके प्रति किस प्रकार का वातावरण बनाया। जिस कारण इतनी कम अवधि में ही **धन्ना सेठ कुबेर** हो गए देश के लोग अमीर है। यह हमारे लिए गर्व की बात है और मजबूत अर्थ व्यवस्था समृद्धता की धौतक है। आज 138 अरब

पति है तो कल इनकी संख्या में और वृद्धि होगी देश के आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए इनकी संख्या में लगाताार वृद्धि हो इसकी हम कामना करते है **लेकिन देखना यह है कि उदारवादी आर्थिक नीतियों का लाभ एक वर्ग विशेष तो नहीं उठा रहा है** क्या धन का असमान विवरण जो नही हो रहा है विकास तो हो रहा है परन्तु किसका ? 20 प्रतिशत औद्योगिक घरानों के पास देश का 80 प्रतिशत धन है वही 80 प्रतिशत लोगो के पास देश का 20 प्रतिशत धन है पांच सितार होटल गगन चुम्बी अट्टालिकाओं और बी.आई.पी. सेज और आवासीय कालोनियों की चमक में झोपड पट्टियां कहां दिखाई देती है? बडे–बडे औद्योगिक घराने देश की शान है। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए की देश की 70 फीसदी से अधिक जनता गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है आज भी देश में ऐसे करोडो परिवार है जिन्हे दो वक्त की रोटी नसीब नही होती खाद्य महंगाई की दर बढ़ती जा रही है देश में उत्पादन की कोई कमी नहीं है। निर्यात भी हो रहा है लेकिन कीमते इतनी ज्यादा है की आसमान से उतरने का नाम ही नही ले रही है। अर्थिक तेजी से तंग आकर लोग दिहाड़ी मजदूर उनके परिवार और किसान आत्महत्याएं कर रहे है। गरीबी/बेरोजगारी भुखमरी कुपोषण एवं बाल मृत्यु के आंकडे भी चिन्ताजनक है दूसरे कई देशों की तुलना में हमारे देश में बीमार और भूखे लोगों की संख्या ज्यादा है इस सबके लिए हमारी देश की जनसंख्या ही जिम्मेदार है एक अरब से अधिक जनसंख्या वाले देश मे कुछ समस्याऐं होना स्वभाविक है। गरीबों के नाम पर बनाई जा रही अनेक योजनाओं का लाभ गरीब व आदिवासी लोगों को नही मिल रहा है उन्हे। बुनियादी अधिकारों से भी वंचित किया जा रहा है देश की आर्थिक नीतियों का लाभ केवल पूंजीपति ही उठा रहे है इस असन्तुलन को दूर करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिऐ। गरीबी आज भी भारत की अन्तर्राष्ट्रीय पहचान है, पश्चमी देश आज भी भारत की गरीबी का मजाक उडाते है। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक प्रौद्योगिकी–इत्यादि के सभी हिस्सो को प्रभावित किया है। इसके कुछ प्रभाव सकारात्मक रहे है तो कुछ नकारात्मक भी रहे है।

वैश्वीकरण, कुटीर उद्योग धन्धे व स्वरोजगार

यदि हम आर्थिक स्तर पर देखे तो वैश्वीकरण ने अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढ़ाचे को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है वही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की उन्नत तकनीक बडी पूँजी आधुनिक प्रबन्धन के आक्रमक प्रचार एवं सरकारी संस्थाओं ने स्थानीय कुटीर उद्योग धन्धों को अलाभकारी बनाकर बाजार से बाहर कर दिया है। कही पर्यावरण के नाम पर, कही बालश्रम के प्रयोग के नाम पर, कही अस्वास्थ्य पस्थितियों के सृजन के नाम पर, तो कही विकास के नाम पर सरकार ने छोटे उद्योगो को नियंत्रित करना प्रारंभ कर दिया है इससे देश में बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। लुभावने विज्ञापनों एवं आक्रमक पंच लाईनों के माध्यम से बहुर्राष्ट्रीय निगमों ने सम्पन्न वर्ग पर मानसिक आधिपत्य जमा लिया है। उन्हें प्रत्येक विदेशी वस्तु जिसे वे ब्राण्डेड कहते है प्रस्थिति प्रतीक लगती है जिससे वे रेहड़ी, फेरीवालों को अतिक्रमणकारी, अवैध तथा विकास में बाधक समझते है।

वैश्वीकरण, बहुलता तथा सांस्कृतिक विविधता

जहा एक और वैश्वीकरण ने पाश्चात्य सांस्कृतिक समरूपीकरण को बढ़ावा दिया है वही एक और भारतीय सांस्कृति विविधता को भी प्रभावित किया है। भाषा, वेश–भूषा, आदते, विचार, व्यवहार आदि पश्चिमी ढंग के होते चले जा रहे है भारत में पूर्व में प्रचलित संयुक्त परिवार प्रणाली के एकल परिवार प्रणाली का सृजन हुआ है। जिससे पारिवारिक विघटन व सामाजिक मुल्यों का ह्रास भी हुआ है। इन सबका प्रभाव यह हुआ कि भारत भी समरूपी विश्व व्यवस्था की तरफ हल्के प्रतिरोध से जाने लगा। आज देश में अनेक बोलियों मृत प्रायः है। भाषा में अंग्रेजी का बोलबाला है। बहुत सी परम्परागत रीतियां अपना अस्तित्व खोती जा रही है। वैश्विक उत्सव एवं त्यौहार अपनी पैठ बढ़ा रहे है। जिनका देशज भावनाओं एवं संवेदनाओं से कोई लेना देना नहीं है। इन सबसे बहुराष्ट्रीय निगमों के सन्दर्भ में प्रतिरोध की संस्कृति समाप्त हो रही है। तथा उन्हें लूट की खुली छूट मिल रही है और एक नवीन प्रकार का औपनिवेशीकरण प्रारम्भ हो चुका है।

वैश्वीकरण एवं महिलायें

भारत विश्व का बडा जनसख्या वाला देश है। भारतीय समाज में जहा एक ओर महिलाओं को शिक्षा रोजगार एवं गतिशीलता में वृद्धि हुई है व सामाजिक–आर्थिक सन्दर्भ में लिंग भेद में कमी आना महिला सशक्तीकरण का सकारात्मक पहलू है। महिलायें अब न केवल अध्यापन, चिकित्सा एवं स्वागती पेशे तक सीमित है अपितु वे पत्रकारिता फैशन, उद्योग, विमान परिचारिका, अभियांत्रिकी, विज्ञान, रक्षा, न्यायिक एवं सामान्य प्रशासन के क्षेत्र में भी आगे बढ रही है। वैश्वीकरण ने महिलाओं को पुरूषों के बराबर अवसर प्रदान किये है। वही अखबारों पत्र–पत्रिकाओं, सिनेमा, टीवी, इन्टरनेट एवं विज्ञापनों में भारतीय महिलाओं को परम्परागत छवि से बाहर निकाल कर उन्मुक्तता की ओर अग्रसर किया जा रहा है। 13 जनवरी, 2010 को देश की राजधानी दिल्ली में इण्डिया टुडे के प्रमुख संवाददाता मिहिर श्रीवास्तव तथा फोटो एडीटर बन्दीप सिंह ने एक स्टिंग ऑपरेशन से स्पष्ट किया है कि भारत का वर्तमान में एक भिन्न प्रकार के वैश्वीकरण से सामना हो रहा है, जिसने सामाजिक संस्कारो और वर्जनाओं की सीमाओं को धुंधला कर दिया है।

वैश्वीकरण गांव तथा गरीब

वैश्वीकरण ने भारतीय गांवों की तस्वीर बदली है नगदी फसले, नई तकनीकि बैंकिग प्रणाली तक पहुॅच, प्रौद्योगिकी का प्रयोग तथा मनरेगा जैसे लोकहितकारी कार्यक्रमों ने गॉव को बदलने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल संख्या अधिक है इससे स्पष्ट होता है कि गांवों में वैश्वीकरण की नीतियों का लाभ विशेष वर्ग तक ही सीमित रहा, वंचित एवं सम्पन्न के मध्य की खाई बढ़ती जा रही है। प्रो. राजीव गुप्ता के अनुसार ये सब, "उत्पादक शक्तियों के वितरण की असमानता एवं वैश्वीकरण की अन्तःसम्बन्द्धता के फलस्वरूप हो रहे परिवर्तनों का असर है जिससे श्रमिक जनसंख्या का दरिद्रीकरण एवं कॉर्पोरेट पूंजीपति धनाढ्यों की संख्या में तीव्र वृद्धि विपरित प्रकृति की घटनाओं के रूप में घटित हुई है।"

वैश्वीकरण पर्यावरण एवं जैव–विविधता

वैश्वीकरण, पर्यावरण एवं जैव–विविधता पर भी वैश्वीकरण का प्रभाव पडा है जिससे तीव्र औद्योगिकरण के लिए अपनाये गये सभी उपायों ने गंभीर पारिस्थितिकीय असंतुलन उत्पन्न कर दिये है। वनों का विनाश, जल का अतिदोहन, भूमि–जल एवं वायु में विषाक्तता की वृद्धि, शहरों का अनियंत्रित विकास, प्राकृतिक सम्पदा पर देशज जनता का विस्थापन, गरीबों की संख्या में वृद्धि, समाज में असंतोष में वृद्धि आदि पर प्रभाव पड़ा है वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने जहाँ एक ओर आर्थिक विकास को बढ़ाया है

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. समाजशास्त्रीय शाखाओं का परिचय :– डॉ. गोपाल कृष्ण अग्रवाल
2. भारतीय जनजातियाँ :–संरचना एवं विकास डॉ. हरिशचन्द्र उप्रेती
3. वैश्विक आर्थिक संकट और भारतीय अर्थ व्यवस्था :– डॉ. ओ.पी शर्मा
4. मोघदम वेलेन्टाइन एम., ग्लोबलाईजेशन एण्ड सोशल मूवमेन्टस, रोमन एण्ड लिटिल फील्ड पब्लिशर्स, इंक. यू. एस.,
5. कुमार नागेश, इकॉनोमिक एण्ड पोलिटीकल वीकली,
6. महला, अरविन्द कुमार, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव
7. इन्टरनेट
8. इण्डिया टुडे
9. योजना
10. कुरूक्षेत्रा

❖◆❖